

सत्यमेव जयते

विद्युत मंत्रालय
MINISTRY OF
POWER

साप्ताहिक सूचना पत्र

दिनांक 14.11.2026 से 20.11.2026

17वाँ संस्करण

सभी संस्करण यहाँ पढ़े।



श्री मनोहर लाल

माननीय केंद्रीय विद्युत तथा आवासन एवं शहरी कार्य मंत्री

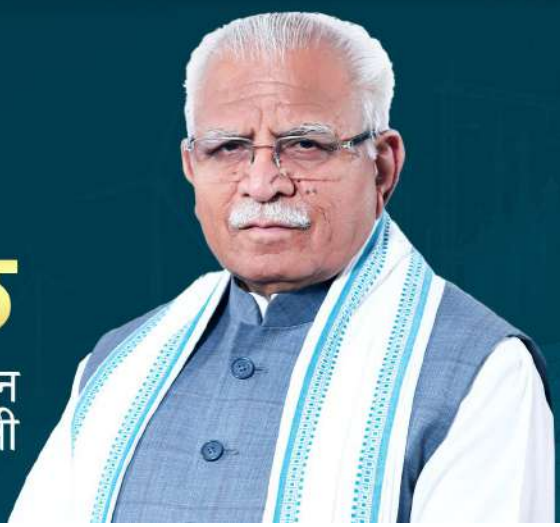

विद्युत मंत्रालय
MINISTRY OF
POWER

सत्यमेव जयते

सप्ताह की प्रमुख उपलब्धियाँ

1. **228.18 गीगावाट** की अधिकतम विद्युत मांग बिना किसी कमी के पूरी की गई

2. **प्रधानमंत्री** ने कर्नाटक में **POWERGRID** की दो पारेषण परियोजनाओं का उद्घाटन किया, दो अन्य परियोजनाओं की आधारशिला रखी

3. **विद्युत मंत्रालय का मंडप, IITF 2026** में विद्युत क्षेत्र की एक दशक की पहलों और उपलब्धियों को प्रदर्शित कर रहा है

4. GRID-INDIA ने POWERGRID से CTUIL के अधिग्रहण के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए

5. **BBMB और CWPRS** ने सतलुज एवं ब्यास नदियों तथा संबंधित जलमार्गों के लिए स्टेज-डिस्चार्ज कर्व के विकास और सत्यापन हेतु समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए

6. PFC की CMD श्रीमती परमिंदर चोपड़ा को बिजनेस टुडे Most Powerful Women 2026 की सूची में सम्मान



साप्ताहिक सूचना पत्र

14.11.2026 से 20.11.2026

विद्युत मंत्रालय
MINISTRY OF
POWER

सत्यमेव जयते

19 नवंबर 2026

228.18 गीगावाट की अधिकतम विद्युत मांग बिना किसी कमी के पूरी की गई

नीचे दिए गए चार्ट में 13 नवंबर से 19 नवंबर, 2026 तक प्रतिदिन पूरी की गई अधिकतम विद्युत मांग तथा दर्ज की गई विद्युत की कमी दर्शाई गई है।





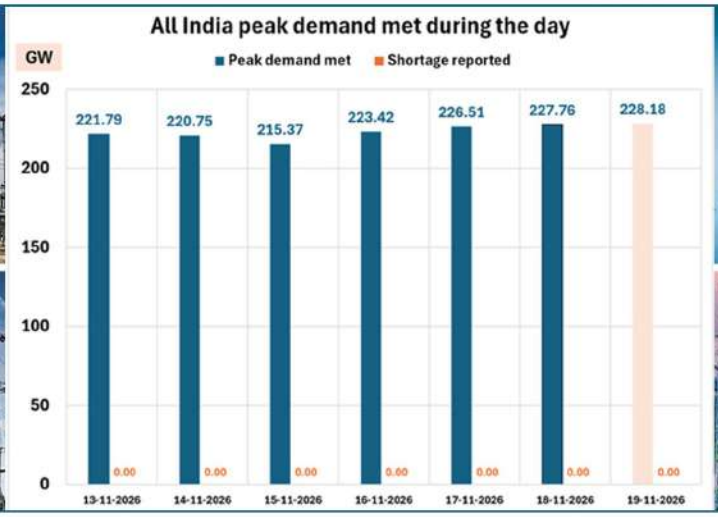





साप्ताहिक अधिकतम मांग के समय कुल विद्युत उत्पादन

Generation source	Generation (GW)	Share of Total generation (%)
Gas / Liquid fuel	1.5	0.7%
Hydro	7.7	3.3%
Nuclear	6.7	2.9%
Coal and Lignite	136.8	58.9%
Wind	8.2	3.5%
Solar	67.4	29.0%
Storage (PSP&BESS)	0.0	0.0%
Others	3.8	1.6%
Transnational Import	0.0	0.0%
TOTAL	**232.2**	**100.0%**
Transnational Export	0.8	0.3%

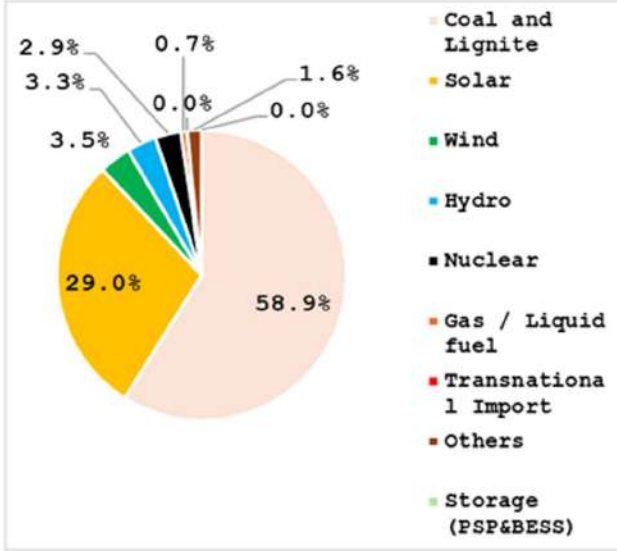

पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में पूरी की गई अखिल भारतीय अधिकतम विद्युत मांग और ऊर्जा खपत में क्रमशः 14% और 11.5% की वृद्धि दर्ज की गई।

साप्ताहिक सूचना पत्र

14.11.2026 से 20.11.2026

विद्युत मंत्रालय
MINISTRY OF
POWER
सत्यमेव जयते

13 नवंबर 2026

प्रधानमंत्री ने कर्नाटक में POWERGRID की दो पारेषण परियोजनाओं का उद्घाटन किया, दो अन्य परियोजनाओं की आधारशिला रखी





माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने POWERGRID की दो पारेषण परियोजनाओं—"कर्नाटक में कोप्पल-II (चरण-A एवं B) और गडग-II (चरण-A) में नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र (चरण-II) के एकीकरण हेतु पारेषण योजना" तथा "कर्नाटक के बीदर में सौर ऊर्जा क्षेत्र (2500 मेगावाट) के लिए पारेषण योजना"—का उद्घाटन किया।

उन्होंने POWERGRID की "कर्नाटक में दावणगेरे/चित्रदुर्ग और बेल्लारी नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र के एकीकरण हेतु पारेषण योजना" तथा "दावणगेरे (0.25 गीगावाट) और बेल्लारी (2.75 गीगावाट) में अतिरिक्त नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता के एकीकरण हेतु पारेषण प्रणाली को सुदृढ़ करने" संबंधी परियोजनाओं की आधारशिला भी रखी। इस अवसर पर कर्नाटक की माननीय राज्यपाल डॉ. सुधा यादव और कर्नाटक के माननीय मुख्यमंत्री श्री डी. के. शिवकुमार सहित अन्य वरिष्ठ गणमान्य व्यक्ति भी उपस्थित थे।

ये योजनाएँ कर्नाटक से देशभर के मांग केंद्रों तक नवीकरणीय ऊर्जा के पारेषण की ग्रिड क्षमता को सुदृढ़ करेंगी।

विद्युत मंत्रालय
MINISTRY OF
POWER
सत्यमेव जयते

16 नवंबर 2026

विद्युत मंत्रालय का मंडप, IITF 2026 में विद्युत क्षेत्र की एक दशक की पहलों और उपलब्धियों को प्रदर्शित कर रहा है





भारत मंडपम, नई दिल्ली में आयोजित 45वें भारत अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेले (IITF) 2026 में विद्युत मंत्रालय का मंडप पिछले एक दशक में विद्युत क्षेत्र की पहलों और उपलब्धियों को प्रदर्शित कर रहा है। मेले में आने वाले दर्शकों के लिए विद्युत क्षेत्र की पहलों को प्रौद्योगिकी के माध्यम से सरल और रोचक बनाने के उद्देश्य से इस मंडप में इंटरैक्टिव प्रदर्श, इमर्सिव ज़ोन, काइनेटिक वॉल, एनामॉर्फिक 3D डिस्प्ले, रोटेटिंग LED, वर्चुअल रियलिटी (VR) मॉडल, 3D परियोजना मॉडल और ऊर्जा-कुशल उपकरणों तथा स्मार्ट ऊर्जा समाधानों को प्रदर्शित करने वाला एक स्मार्ट होम शामिल है।

मंडप का उद्घाटन विद्युत मंत्रालय के सचिव श्री पंकज अग्रवाल ने किया। इस अवसर पर मंडप से संबंधित एक पुस्तिका का भी विमोचन किया गया। इस अवसर पर डॉ. साईबाबा दरबामुल्ला, अपर सचिव (विद्युत मंत्रालय), सुश्री रीतू जैन, आर्थिक सलाहकार, विद्युत मंत्रालय, श्री वामसी रामा मोहन बुर्रा, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, POWERGRID, POWERGRID के निदेशक मंडल के सदस्य तथा POWERGRID, NTPC, NHPC, PFC, REC, SJVN, THDC, EESL और BEE के वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे।

यह मंडप विद्युत मंत्रालय के विभिन्न संगठनों को भारत के विद्युत अवसंरचना को सुदृढ़ करने और एक सतत तथा ऊर्जा-सुरक्षित राष्ट्र के दृष्टिकोण को आगे बढ़ाने में उनके योगदान को प्रदर्शित करने के लिए एक साझा मंच प्रदान करता है।
इस मंडप का अवलोकन 27 नवंबर, 2026 तक किया जा सकता है।





साप्ताहिक सूचना पत्र

14.11.2026 से 20.11.2026

विद्युत मंत्रालय
MINISTRY OF
POWER
सत्यमेव जयते

19 नवंबर 2026

GRID-INDIA ने POWERGRID से CTUIL के अधिग्रहण के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए



पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (POWERGRID) से सेंट्रल ट्रांसमिशन यूटिलिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (CTUIL) की 100% चुकता इक्विटी शेयर पूंजी के अधिग्रहण के लिए ग्रिड कंट्रोलर ऑफ इंडिया लिमिटेड (GRID-INDIA) द्वारा शेयर खरीद समझौते (SPA) पर तीनों कंपनियों के संबंधित निदेशक मंडलों के सदस्यों की उपस्थिति में हस्ताक्षर किए गए। यह भारत सरकार के विद्युत मंत्रालय के निर्देशों के अनुपालन में प्रस्तावित अधिग्रहण की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है।

प्रस्तावित अधिग्रहण भारत के विद्युत क्षेत्र के संचालन संबंधी संस्थागत ढाँचे को सुदृढ़ करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इसके माध्यम से प्रणाली संचालन और पारेषण योजना के कार्यों को एकीकृत संस्थागत ढाँचे के अंतर्गत लाने की परिकल्पना की गई है, जिससे बेहतर समन्वय, एकीकृत योजना और भारतीय विद्युत प्रणाली का अधिक प्रभावी विकास संभव होगा।

हस्ताक्षर समारोह में POWERGRID, GRID-INDIA और CTUIL के निदेशक मंडलों के सदस्य तथा वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। उनकी उपस्थिति इस महत्वपूर्ण संस्थागत पहल के सफल कार्यान्वयन के प्रति तीनों संगठनों की सामूहिक प्रतिबद्धता को दर्शाती है।

विद्युत मंत्रालय
MINISTRY OF
POWER
सत्यमेव जयते

19 नवंबर 2026

BBMB और CWPRS ने सतलुज एवं ब्यास नदियों तथा संबंधित जलमार्गों के लिए स्टेज-डिस्चार्ज कर्व के विकास और सत्यापन हेतु समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए



भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड (BBMB), चंडीगढ़ और केंद्रीय जल एवं विद्युत अनुसंधान स्टेशन (CWPRS), पुणे ने CWPRS, पुणे में तकनीकी सहयोग की शुरुआत करते हुए भारत सरकार के जल शक्ति मंत्री माननीय श्री सी. आर. पाटिल तथा जल शक्ति मंत्रालय के माननीय राज्य मंत्री श्री राज भूषण चौधरी की उपस्थिति में समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए और उसका आदान-प्रदान किया।

इस सहयोग के अंतर्गत सतलुज और ब्यास नदियों के महत्वपूर्ण एवं नियंत्रण खंडों, अंतरराज्यीय संपर्क बिंदुओं, नंगल हाइडल चैनल (NHC) और भाखड़ा मेन लाइन (BML) पर स्टेज-डिस्चार्ज कर्व के विकास और सत्यापन के लिए तकनीकी सहयोग की परिकल्पना की गई है। इसके अतिरिक्त, इससे संबंधित अन्य जलगतिकीय और जलवैज्ञानिक अध्ययन एवं गतिविधियाँ भी की जाएँगी।

विद्युत मंत्रालय
MINISTRY OF
POWER
सत्यमेव जयते

19 नवंबर 2026

PFC की CMD श्रीमती परमिंदर चोपड़ा को बिजनेस टुडे Most Powerful Women 2026 की सूची में सम्मान



पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड (PFC) की अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (CMD) श्रीमती परमिंदर चोपड़ा को कॉरपोरेट और व्यावसायिक क्षेत्र में उनके उत्कृष्ट नेतृत्व तथा योगदान के लिए बिज़नेस टुडे द्वारा BT मोस्ट पावरफुल वुमन 2026 के रूप में सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार श्रीमती परमिंदर चोपड़ा को बिज़नेस टुडे के मुख्य परिचालन अधिकारी श्री आलोक नायर ने प्रदान किया। BT मोस्ट पावरफुल वुमन पुरस्कार उन महिला नेतृत्वकर्ताओं के योगदान का सम्मान करते हैं, जो अपने दृष्टिकोण, दृढ़ संकल्प और उपलब्धियों के माध्यम से कॉरपोरेट जगत को नया स्वरूप दे रही हैं, व्यावसायिक विकास को गति प्रदान कर रही हैं और अगली पीढ़ी को प्रेरित कर रही हैं। ये पुरस्कार नेतृत्व में महिलाओं की बढ़ती भूमिका तथा व्यावसायिक उत्कृष्टता और आर्थिक प्रगति में उनके योगदान को मान्यता देते हैं।

यह सम्मान PFC में श्रीमती परमिंदर चोपड़ा के विशिष्ट नेतृत्व और भारत के विद्युत एवं अवसंरचना क्षेत्रों के वित्तपोषण में संगठन की भूमिका को सुदृढ़ करने में उनके योगदान को मान्यता देता है। उनकी यह उपलब्धि आकांक्षी महिला नेतृत्वकर्ताओं के लिए प्रेरणा है और भारत की विकास गाथा को आकार देने में महिलाओं के बढ़ते प्रभाव को रेखांकित करती है।

विद्युत मंत्रालय
MINISTRY OF
POWER

सत्यमेव जयते

इस सप्ताह के प्रमुख समाचार

हिंदुस्तान

(19 नवंबर, 2026)

नेपाल भारत से करेगा 350 मेगावाट बिजली का आयात

काठमांडू, एजेंसी। नेपाल को सर्दी में भारत से 350 मेगावाट तक बिजली आयात करने की मंजूरी मिल गई है। हाल ही में आई बाढ़ से कई जलविद्युत परियोजनाओं को नुकसान पहुंचा है और जलविद्युत उत्पादन में भी कमी आई है, जिसके चलते घरेलू बिजली की मांग को पूरा करने के लिए यह कदम उठाया गया है।

नेपाल विद्युत प्राधिकरण के अधिकारियों ने बताया कि भारत के विद्युत मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण ने प्राधिकरण को भारतीय ऊर्जा विनिमय से प्रतिस्पर्धी दरों पर बिजली खरीदने की अनुमति दी है। इसके तहत वे दिन में 17 घंटे तक बिजली ले सकते हैं। नेपाल विद्युत प्राधिकरण के प्रबंध निदेशक दीर्घायु कुमार श्रेष्ठ ने बताया कि यह मंजूरी 17 नवंबर से 31 जुलाई, 2027 तक प्रभावी रहेगी। इससे नेपाल को बिजली की मांग, घरेलू उत्पादन के बीच के मौसमी अंतर को प्रबंधित करने में मदद मिलेगी।

नेपाल के पीएम से भारतीय राजदूत की मुलाकात

काठमांडू। भारत के राजदूत सुधाकर दलेला ने बुधवार को नेपाल के प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह से मुलाकात की और भारत की उनकी प्रस्तावित आधिकारिक यात्रा की तैयारियों पर चर्चा की। प्रधानमंत्री सचिवालय के अनुसार, सिंह दरबार में हुई मुलाकात के दौरान दलेला ने शाह को बताया कि उनके भारतीय समकक्ष नरेंद्र मोदी के साथ होने वाली द्विपक्षीय बातचीत ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण होगी।

दैनिक सवेरा टाइम्स

(19 नवंबर, 2026)

रणजीत सागर बांध परियोजना से बिजली उत्पादन शुरू

सवेरा न्यूज/सुभाष/राकेश माधोपुर/शाहपुरकंडी : रणजीत सागर बांध परियोजना की दूसरी इकाई शाहपुर कंडी बैराज बांध के निर्माण कार्य को तेजी से करवाने के लिए न नहरों में सफाई के साथ अन्य कार्य करने के लिए पंजाब सरकार के जल स्त्रोत विभाग ने रणजीत सागर बांध परियोजना से बिजली उत्पादन के साथ सिंचाई के लिए भी नीचले क्षेत्रों में पानी को छोडना बंद कर दिया था व अब लगभग 25 दिनों की बंदी के बाद जल स्त्रोत विभाग ने बांध परियोजना से बिजली उत्पादन के साथ सिंचाई के लिए नहरों में पानी को छोडना शुरू कर दिया है, जिससे रणजीत सागर बांध परियोजना की झील में जलस्तर में भी बढौतरी हुई है। बंदी के समय बांध परियोजना की झील में जलस्तर 506 मीटर तक रहा गया था, जो 25 दिनों की बंदी के बाद जलस्तर बढ कर 508.21 मीटर तक आ गया है। इस समय भी नीचले क्षेत्रों में सिंचाई के लिए पानी की मांग कम होने से बिजली उत्पादन को रूक रूक कर लिया जा रहा है, जिससे प्रतिदिन केवल चार से पांच घंटों तक आरएसडी बांध की चार टरबाईनों में से दो टरबाईनों को तीन सौ मेगावाट क्षमता से चल कर प्रतिदिन 26 लाख बिजली यूनिट उत्पादन ले कर शाहपुर कंडी बैराज बांध की झील में 14563 क्यूसिक पानी का बहाव छोडा जा रहा है, जिससे शाहपुर कंडी बैराज बांध की झील का जलस्तर 402. 23 मीटर तक आ गया है, जबकि शाहपुर कंडी बैराज बांध की झील में अधिकतम जलस्तर 404.50 मीटर तक रखने की क्षमता है। बांध प्रशासन अनुसार, इस समय शाहपुर कंडी बैराज बांध की झील में पर्याप्त मात्रा में पानी स्टोर हो चुका है, जिससे आगामी दिनों में नीचले क्षेत्रों में सिंचाई के लिए पानी की कोई समस्या पैदा नहीं होगी।



आरएसडी झील

हिंदुस्तान

(19 नवंबर, 2026)

तांकुल बिजली परियोजना को केंद्र सरकार की मंजूरी

देहरादून, मुख्य संवाददाता। तांकुल जल विद्युत परियोजना को केंद्र ने फॉरेस्ट क्लीयरेंस दे दी है।

धारचूला में 12 मेगावाट क्षमता का तांकुल स्माल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट तैयार किया जाएगा। केंद्र सरकार से राज्य के लगातार तीसरे हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट को मंजूरी दी है। इससे पहले त्यूनी प्लासू, सरकारी ग्योल रसियाबगड़ हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट को मंजूरी दी गई थी। उत्तराखंड के लिए ये प्रोजेक्ट बड़ी राहत बनेंगे। केंद्र ने उत्तराखंड के 2124 मेगावाट क्षमता के 21 प्रोजेक्ट पर रोक लगाई हुई है। इस संबंध में यूजेवीएनएल के एमडी अजय कुमार सिंह ने बताया कि तांकुल पावर प्रोजेक्ट को केंद्र की फॉरेस्ट क्लीयरेंस मिल गई है।

विद्युत मंत्रालय
MINISTRY OF
POWER

सत्यमेव जयते

इस सप्ताह के प्रमुख समाचार

हिंदुस्तान
(18 नवंबर, 2026)

धुरियापार में 15 हजार करोड़ से लगेगा ग्रीन अमोनिया का प्लांट

हि अच्छी खबर

गोरखपुर, वरिष्ठ संवाददाता। गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे के दोनों तरफ विकसित हुए धुरियापार औद्योगिक क्षेत्र में ऊर्जा क्षेत्र की इंटरनेशनल कंपनी ने 15 हजार करोड़ के निवेश का प्रस्ताव दिया है। ऊर्जा क्षेत्र की आशी कंपनी एसीएमई ग्रुप धुरियापार में 150 से 200 एकड़ जमीन में ग्रीन अमोनिया का प्लांट स्थापित करना चाहती है। इसके लिए प्रतिनिधियों की टीम धुरियापार के सेक्टर पांच पहुंची और उपलब्ध भूमि की स्थिति देखी।



प्रतीकात्मक फोटो

- ऊर्जा क्षेत्र की कंपनी एसीएमई ग्रुप ने 15 हजार करोड़ रुपये की परियोजना में दिलचस्पी दिखाई
- कंपनी के प्रतिनिधियों ने गीडा के अधिकारियों साथ किया दौरा, कंपनी को चाहिए 150 से 200 एकड़ जमीन

कंपनी की तरफ से गीडा को जो प्रस्ताव दिया गया है, उसके मुताबिक निवेश से 1000 लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार मिलेगा। गीडा प्रशासन द्वारा प्रस्तावित जमीन प्रतिनिधियों को दिखाई गई है। गीडा के जिम्मेदारों का दावा है कि इस परियोजना के आने से धुरियापार की औद्योगिक गतिविधियों को बड़ा विस्तार मिल सकता है। ग्रीन अमोनिया का इस्तेमाल मुख्य रूप से उर्वरक बनाने में किया जाता है। गोरखपुर में भी इसके उत्पादन की योजना है। इससे खाद उद्योग को नई तकनीक और स्वच्छ ऊर्जा आधारित उत्पादन से जोड़ने का रास्ता खुलेगा।

एसीएमई ग्रुप ने ग्रीन एनर्जी के क्षेत्र में अपनी अलग पहचान बनाई है। 2003 में दूरसंचार कंपनियों के मोबाइल टावरों को ऊर्जा प्रबंधन समाधान उपलब्ध कराने से कारोबार शुरू करने वाले इस समूह ने बाद में सौर और पवन ऊर्जा के क्षेत्र में विस्तार किया। अब कंपनी ग्रीन हाइड्रोजन और ग्रीन अमोनिया के उत्पादन में निवेश कर रही है। ओडिशा के गोपालपुर में जापान की आइएचआइ कारपोरेशन के साथ ग्रीन अमोनिया संयंत्र लगाने की योजना है। इसकी उत्पादन क्षमता चार लाख मीट्रिक टन प्रतिवर्ष है। गीडा के एसीईओ रामप्रकाश के अनुसार, कंपनी के प्रतिनिधियों ने धुरियापार में उपलब्ध जमीन का निरीक्षण किया है। उन्हें जितनी जमीन की जरूरत होगी, मुहैया करा दी जाएगी।

बिजली व जहाजों का ईंधन बनाने में उपयोग

ग्रीन अमोनिया को भविष्य की स्वच्छ ऊर्जा व्यवस्था का महत्वपूर्ण हिस्सा माना जा रहा है। सामान्य अमोनिया के उत्पादन में जीवाश्म ईंधन का इस्तेमाल होता है, जबकि ग्रीन अमोनिया नवीकरणीय बिजली से तैयार हाइड्रोजन और हवा से मिलने वाली नाइट्रोजन से बनाया जाता है। इससे कार्बन उत्सर्जन कम होता है। खाद के अलावा इसका इस्तेमाल रसायन उद्योग, बिजली उत्पादन और भविष्य में जहाजों के ईंधन के रूप में भी बढ़ने की संभावना है।

बिज़नेस रेमेडीज
(14 नवंबर, 2026)

भारत की बिजली उत्पादन क्षमता बढ़कर 560 गीगावाट पहुंची, 55 प्रतिशत हिस्सेदारी गैर-जीवाश्म ईंधन स्रोतों की

नई दिल्ली | एजेंसी

भारत की कुल स्थापित बिजली उत्पादन क्षमता अक्टूबर 2026 में बढ़कर करीब 560 गीगावाट पहुंच गई है, जो 2014 में दर्ज 249 गीगावाट की क्षमता के मुकाबले दोगुने से भी अधिक है। खास बात यह है कि देश की कुल बिजली उत्पादन क्षमता में गैर-जीवाश्म ईंधन स्रोतों की हिस्सेदारी बढ़कर 55 प्रतिशत हो गई है। शुक्रवार को जारी एक आधिकारिक फैक्टशीट में यह जानकारी दी गई।

आंकड़ों के मुताबिक, 31 जुलाई 2026 तक भारत की गैर-जीवाश्म ईंधन आधारित बिजली उत्पादन क्षमता 308 गीगावाट थी। इसके साथ ही भारत नवीकरणीय ऊर्जा की स्थापित क्षमता के मामले में दुनिया में तीसरे स्थान पर पहुंच गया है। वहीं, जुलाई 2024 से जून 2026 के बीच देश के नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में 63.7 अरब डॉलर का निवेश किया गया। भारत में नवीकरणीय ऊर्जा के विस्तार में सौर ऊर्जा सबसे बड़ा योगदान दे रही है। 31 अक्टूबर 2026 तक देश की स्थापित सौर ऊर्जा क्षमता करीब 175 गीगावाट पहुंच गई, जबकि वर्ष 2014 में यह महज 2.8 गीगावाट थी। वर्ष 2025 में भारत ने 37 गीगावाट से अधिक सौर ऊर्जा क्षमता जोड़ी। इसके साथ ही भारत उस साल दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सौर ऊर्जा क्षमता विस्तार वाला बाजार बन गया। इस दौरान अमेरिका ने 34 गीगावाट की नई सौर ऊर्जा क्षमता जोड़ी थी। फैक्टशीट में कहा गया है कि सरकार की पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना भी रूफटॉप सोलर के विस्तार में अहम भूमिका निभा रही है। फरवरी 2024 में शुरू की गई इस योजना के लिए 75,021 करोड़ रुपए का बजट निर्धारित किया गया था, जिसका लक्ष्य देश के एक करोड़ घरों तक रूफटॉप सोलर की सुविधा पहुंचाना है।

दैनिक जागरण
(18 नवंबर, 2026)

यूपी के 5 लाख घरों पर लगेंगे रूफटॉप सोलर संयंत्र, केंद्र को भेजा प्रस्ताव

- पीएम सूर्य घर योजना के तहत 750 मेगावाट अतिरिक्त सौर ऊर्जा क्षमता विकसित करने की तैयारी, 3,750 करोड़ रुपये की परियोजना

पायनियर समाचार सेवा। लखनऊ



प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत योगी सरकार ने प्रदेश के 5 लाख घरेलू विद्युत उपभोक्ताओं के घरों पर रूफटॉप सोलर संयंत्र स्थापित करने की महत्वाकांक्षी योजना तैयार की है। इसके लिए उपयोगिता आधारित एकत्रीकरण मॉडल के अंतर्गत केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजा गया है। इस परियोजना के माध्यम से प्रदेश में लगभग 750 मेगावाट अतिरिक्त सौर ऊर्जा क्षमता विकसित की जाएगी। इस प्रस्तावित योजना के तहत 5 लाख घरों में से 50 प्रतिशत घरों पर 1 किलोवाट तथा शेष 50 प्रतिशत घरों पर 2 किलोवाट क्षमता के सोलर संयंत्र लगाए जाएंगे। परियोजना की अनुमानित लागत लगभग 3,750 करोड़ रुपये है, जिसमें केंद्र एवं राज्य सरकार की वित्तीय सहायता प्रस्तावित है। योजना का क्रियान्वयन उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड, उसकी विभिन्न विद्युत वितरण कंपनियों एवं उत्तर प्रदेश नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण के समन्वय से किया जाएगा। इस पहल से बड़ी संख्या में घरेलू विद्युत उपभोक्ताओं को सौर ऊर्जा से जोड़ने, बिजली बिल में कमी लाने तथा प्रदेश में स्वच्छ एवं हरित ऊर्जा को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी। वछअ मॉडल के माध्यम से बड़े स्तर पर एकीकृत रूप से सोलर संयंत्रों की स्थापना का मार्ग प्रशस्त होगा।

उल्लेखनीय है कि प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत संचयी रूफटॉप सोलर स्थापनाओं में उत्तर प्रदेश देश में प्रथम स्थान पर है। प्रदेश में अब तक कुल 9,62,866 रूफटॉप सोलर संयंत्र स्थापित किए जा चुके हैं। यह उपलब्धि प्रदेश में सौर ऊर्जा के प्रति बढ़ते जनविश्वास, सरकार के प्रयासों तथा विभिन्न विभागों और विद्युत वितरण कंपनियों के समन्वित कार्यों को दर्शाती है।

यूपी में रूफटॉप सौर ऊर्जा की अपार संभावनाओं को देखते हुए प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के प्रति उपभोक्ताओं में लगातार उत्साह बढ़ रहा है। विद्युत उपभोक्ताओं से अपील की गई है कि वे योजना की निर्धारित अंतिम तिथि 31 मार्च 2027 से पहले आधिकारिक पीएम सूर्य घर पोर्टल पर आवेदन करें और पात्रतानुसार अधिकतम 1.08 लाख रुपये की केंद्रीय एवं राज्य सब्सिडी का लाभ उठाकर अपने घरों पर सोलर संयंत्र स्थापित कराएं। इससे उन्हें बिजली बिल में उल्लेखनीय बचत के साथ स्वच्छ ऊर्जा का लाभ भी मिलेगा।

विद्युत मंत्रालय
MINISTRY OF
POWER

सत्यमेव जयते

इस सप्ताह के प्रमुख समाचार

हिंदुस्तान
(17 नवंबर, 2026)

जल संसाधन के भवनों पर 500 मेगावाट सोलर बिजली का होगा उत्पादन

- जल संसाधन विभाग ने भवनों को चिह्नित कर ऊर्जा विभाग को सूची सौंपी
- पटना, गया, जहानाबाद, नालंदा, सुपौल, मधुबनी, दरभंगा में होगा उत्पादन

पटना, हिब्यू। राज्य के अन्य सरकारी भवनों की तर्ज पर अब जल संसाधन विभाग के भवनों पर भी सोलर बिजली उत्पादित होगी। जल संसाधन ने राज्यभर में ऐसे भवनों को चिह्नित कर लिया है, जहां सोलर बिजली के उत्पादन की संभावना है।

ऊर्जा विभाग के अनुरोध पर जल संसाधन ने ऐसे भवनों की पहचान कर सूची सौंप दी है। आकलन के अनुसार, जल संसाधन के भवनों पर 500 मेगावाट सोलर बिजली उत्पादित होगी। मौजूदा वित्तीय वर्ष में ही इस योजना पर काम शुरू होगा। 2029-30 तक जल संसाधन के भवनों से 500 मेगावाट सोलर बिजली उत्पादन शुरू हो जाएगा। उत्तर बिहार की तुलना में दक्षिण बिहार में ऐसे भवनों की पहचान अधिक की है। सबसे अधिक पटना जिले में बिजली उत्पादित होगी। हार्डीहट के स्टाफ क्वार्टर में 6300 किलोवाट सोलर बिजली उत्पादन की संभावना है। मसौढ़ी निर्वहण कक्ष में 160 किलोवाट बिजली उत्पादित होगी। पटना के अन्य भवनों की छतों पर भी 300 किलोवाट से अधिक सोलर बिजली उत्पादित होगी। जेरुपुरा के कार्यपालक अभियंता प्रमंडल कार्यालय की छत से 15 किलोवाट सोलर बिजली उत्पादित होगी। नालंदा में खंडेकापुर स्टेशन रोड की भवन पर 10 किलोवाट, क्रिकेट स्टेडियम राजगीर के समीप एमवृजीआर में 416 किलोवाट तो राजगीर निरीक्षण भवन की छत पर पांच किलोवाट बिजली उत्पादित होगी। नवादा में मोतनाजे, फिल्टर भवन, वृटिलिटी भवन में 6530 किलोवाट बिजली उत्पादित होगी। गंगाकल आपूर्ति योजना संवेद से 524 किलोवाट तो घोसी कार्यपालक अभियंता कार्यालय की छत पर 30 किलोवाट बिजली उत्पादित होगी। नवादा, गया, जहानाबाद, आदि जिलों के अन्य भवनों पर भी एक से पांच किलोवाट बिजली उत्पादित होगी। भवनों की पहचान करने के क्रम में इसका खास ख्याल रखा है कि आकलन के अनुसार बिजली का उत्पादन हो।

दैनिक सवेरा टाइम्स
(15 नवंबर, 2026)

स्मार्ट तकनीक से घरों में बिजली उपकरणों पर होगा बेहतर नियंत्रण

सवेरा न्यूज़/ कास

नई दिल्ली, 14 नवंबर: घरों में सुविधा, सुरक्षा और बिजली की बचत को बढ़ावा देने के लिए टाटा पावर ने दिल्ली में ईज़ी होम स्वचालन समाधान शुरू किए हैं। इस नई श्रृंखला में स्मार्ट सॉकेट, टच पैनल स्विच, स्मार्ट परिवर्तक और गति संवेदक शामिल हैं। इन उपकरणों को मौजूदा बिजली व्यवस्था से आसानी से जोड़ा जा सकता है। इनके इस्तेमाल के लिए घर में बड़े बदलाव या दीवारों की तोडफोड की जरूरत नहीं होगी। मोबाइल ऐप के जरिए उपभोक्ता दूर से बिजली उपकरणों को नियंत्रित करने, बिजली खपत देखने और उनके संचालन का समय निर्धारित करने में सक्षम होंगे।

इन समाधानों में अधिक भार से सुरक्षा और इंटरनेट के बिना काम करने की सुविधा भी दी गई है। यह पहल कंपनी के 'ईज़ी होम-100 शहर, एक उद्देश्य' अभियान का हिस्सा है, जिसके तहत स्मार्ट घरेलू तकनीक को देशभर में पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है।

द पायनियर
(17 नवंबर, 2026)

इलेक्ट्रिक वाहनों से भारत को हर साल होगी 9.6 लाख करोड़ की बचत

संजय कुमार। गुरुग्राम



इलेक्ट्रिक वाहनों और स्वच्छ ऊर्जा को तेजी से बढ़ावा देना भारत की अर्थव्यवस्था के लिए बड़ी राहत साबित हो सकता है। एक नए ऊर्जा विश्लेषण के मुताबिक, भारत अगर विद्युतीकरण की रफ्तार तेज करता है तो बिल वर्ष 2035 तक जीवाश्म ईंधन के सालाना आयात बिल में 40 प्रतिशत से अधिक की कटौती कर सकता है। इससे देश को हर साल करीब 9.6 लाख करोड़ रुपये की संभावित बचत होगी। वहीं, 2045 तक प्रत्यक्ष जीवाश्म ईंधन आयात को शून्य तक लाने की संभावना जताई गई है। जलवायु एवं ऊर्जा क्षेत्र की शोध संस्था क्लाइमेट कम्पैटिबल फ्यूचर्स की रिपोर्ट के अनुसार, तेज विद्युतीकरण की स्थिति में 2035 तक कच्चे तेल, प्राकृतिक गैस और कोयले का सालाना आयात बिल घटकर 7.4 लाख करोड़ रुपये रह सकता है। इसके विपरीत मौजूदा रफ्तार जारी रहने पर यह बिल 17 लाख करोड़ रुपये तक पहुंचने का अनुमान है। रिपोर्ट में बताया गया है कि तेजी से विद्युतीकरण होने पर 2035 तक देश की कुल ऊर्जा मांग में बिजली की हिस्सेदारी बढ़कर 54 प्रतिशत हो सकती है, जबकि सामान्य परिस्थितियों में यह केवल 32 प्रतिशत रहने का अनुमान है। संस्था के निदेशक डॉ. मनीष राम के अनुसार, भारत को विद्युतीकरण की दिशा में अपनी मौजूदा गति और तेज करने की जरूरत है। घरेलू स्तर पर उत्पादित बिजली से आयातित ईंधन की जगह लेने पर विदेशी मुद्रा की बचत होगी और रुपये पर दबाव भी कम होगा। रिपोर्ट में स्वच्छ बिजली उत्पादन, बैटरी भंडारण, ट्रांसमिशन नेटवर्क और घरेलू विनिर्माण को मजबूत करने की सिफारिश की गई है।

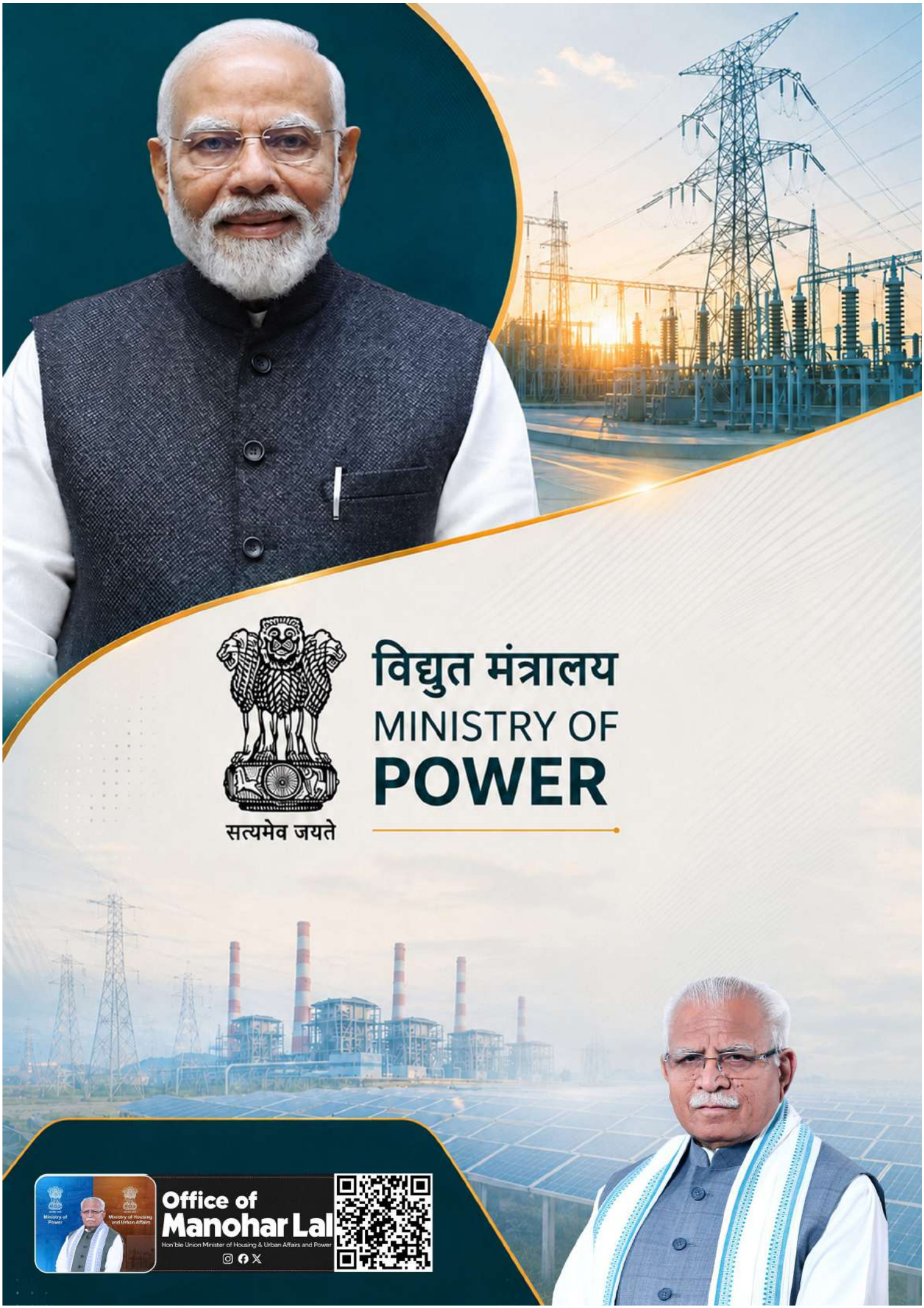
सत्यमेव जयते
विद्युत मंत्रालय
MINISTRY OF
POWER
Office of
Manohar Lal
Hon'ble Union Minister of Housing & Urban Affairs and Power